ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-8* September- 2021
Innovation The Research Concept

सतत ग्रामीण विकास एवं पर्यावरण प्रबन्धः बाँका जिला, (बिहार) का प्रतीक अध्ययन

Sustainable Rural Development and Environment Management: A Case Study of Banka District, (Bihar)

Paper Submission: 14/09/2021, Date of Acceptance: 23/09/2021, Date of Publication: 24/09//2021

उग्रमोहन दास
सहायक प्राध्यापक,
भूगोल विभाग,
डी०एन० सिंह कॉलेज,
भुसिया रजौन, तिलकामांझी
भागलपुर विश्वविद्यालय,
भागलपुर, बिहार, भारत

सारांश

पर्यावरण से अभिप्रेत उन समग्र भौतिक दशाओं एवं मानवीय तथ्यों से है जो पारस्परिक क्रियाओं एवं अन्तर्सम्बन्धों द्वारा पृथ्वी पर जीव-जगत के अस्तित्व एवं नियमन के लिए आवश्यक है। 20 वीं सदी के दशाओं में जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित शोषण-दोहन, नगरीकरण, औद्योगीकरण तथा पर्यावरणीय अवयवों के प्रति उदासीनता एवं उपेक्षाभाव ने पर्यावरण अवनयन की गति को तीव्र कर दिया है जिसका दुष्परिणाम वर्तमान सदी में प्रकट है। वैश्विक तपन, जलवायु परिवर्तन तथा अन्य मानवीय कारकों ने भीषण प्राकृतिक संकट एवं आपदा को जन्म दिया है। परिणामस्वरूप, मानव ही नहीं, समस्त प्राणियों का अस्तित्व खतरे में है। सतत विकास से तात्पर्य समस्त संसाधनों के सम्यक्, बुद्धिसम्मत उपयोग, उपभोग तथा संरक्षण से है ताकि पर्यावरण की अधिकाधिक रक्षा हो सके, उनकी गुणवत्ता बनी रहे, उनमें न्यूनतम हस्तक्षेप हो और भावी पीढ़ी के लिए वे सुरक्षित रह सकें।

भारत ग्राम-बहुल देश है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। ग्रामीण विकास सरकार का परम लक्ष्य है। बिहार राज्य की दक्षिणी सीमा पर झारखण्ड राज्य की सीमा से भागलपुर प्रमंडल के अन्तर्गत बाँका एक पिछड़ा, ग्रामीण, कृषि प्रधान जिला है। इसका आधा दक्षिणी भाग पठारी, उबड़-खाबड़ तथा बंजर भूमि वाला है, जबकि उत्तरी भाग उपजाऊ मैदान है। यहाँ की नदियाँ बरसाती है। नदियों से बालू उत्खनन बड़े पैमाने पर हो रहा है। नदियाँ सिंचाई के लिए सक्षम नहीं हैं । परती, बंजर, बेकार भूमि पर वन संसाधनों की कमी है। इन प्राकृतिक संसाधनों के सम्यक् उपयोग न होने से कृषि आधारित उद्योगों का नितान्त अभाव है। मिट्टी की गुणवत्ता को संरक्षित कर, जलसंसाधनों का सही उपयोग कर, वन संसाधनों के विकास द्वारा इस जिले में विकास की अवधारणा को पूरा किया जा सकता है। प्रस्तुत आलेख का उद्देश्य बाँका जिले में सतत विकास के मार्ग की बाधाओं का आकलन, संभावनाओं की तलाश तथा पर्यावरण-प्रबन्ध की भूमिका को रेखांकित करना है।

Environment means all those physical conditions and human facts which are necessary for the existence and regulation of the life-world on earth through interactions and interrelationships. In the decades of the 20th century, the unexpected increase in population, uncontrolled exploitation-exploitation of natural resources, urbanization, industrialization and indifference and neglect towards environmental components has accelerated the pace of environmental degradation, whose consequences are manifest in the present century. Global warming, climate change and other human factors have given rise to severe natural crises and disasters. As a result, not only human beings but existence of all beings are in danger. Sustainable development refers to the equitable, judicious use, consumption and conservation of all resources so as to

maximize the protection of the environment, maintain their quality, minimize interference and be safe for future generations.

India is a village-dominated country. The economy here is agricultural. Rural development is the ultimate goal of the government. Banka is a backward, rural, agriculturally oriented district under the Bhagalpur division on the southern border of the state of Bihar, adjoining border of the state of Jharkhand. Its southern half is plateau, rough and barren land, while the northern part is fertile plain. The rivers are rainted Excavation of sand from rivers is taking place on a large scale. Rivers are not capable of irrigation. There is a lack of forest resources on fallow, barren, waste lands. Due to non-utilization of these natural resources, there is a complete lack of agro-based industries. Conservation of soil quality, proper use of water resources, development of forest resources can make the concept of development in this district real. The purpose of the present article is to assess the obstacles in the way of sustainable development in Banka district, to explore the possibilities and to underline the role of environmental management.

मुख्य शब्द अभिप्रेत, पर्यावरण, अवनयन, उत्खनन, प्रबन्ध ।
Intent, Environment, Degradation, Mining, Management.

प्रस्तावना

पर्यावरण से अभिप्रेत उन समग्र दशाओं एवं मानवीय तथ्यों से है जो पारस्परिक अन्तःक्रियाओं द्वारा पृथ्वी पर प्राणी-जगत के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। विकास एक बहुआयामी संकल्पना है जिसके आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक, संस्थागत, परिस्थितिकीय, नैतिक आदि विविध आयाम हैं। वस्तुतः विकास एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य समस्त जनसंख्या तथा इसकी जीवन-पद्धति में इस प्रकार का सुधार लाना है ताकि विकास तथा उससे उत्पन्न लाभों के निष्पक्ष वितरण में उनकी सक्रिय, स्वतंत्र तथा सार्थक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। विकास व्यक्ति के सामाजिक तथा आर्थिक दशाओं में गुणात्मक परिवर्तन तथा मात्रात्मक संवृद्धि की एक प्रक्रिया है। पारिस्थितिकीय विकास एक नवीन अवधारणा तथा उपागम है जो पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय नियोजन से घनिष्ट रूप से सम्बन्धित है। इसका लक्ष्य पर्यावरण की गुणवत्ता, जीवन की गुणवत्ता तथा सामाजिक समृद्धि में सुधार लाना तथा वाह्य हस्तक्षेपों के हानिकर प्रभावों से मुक्ति प्रदान करना है। 21वीं सदी के वर्तमान कालखण्ड में जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि, तीव्र नगरीकरण, औद्योगीकरण, संसाधनों के बेरोकटोक शोषण-दोहन तथा पर्यावरणीय अवयवों के प्रति निर्मम उपेक्षा ने पर्यावरण अवनयन की गति को तेज कर दिया है, फलस्वरूप भयावह प्राकृतिक आपदाएँ प्रकट हो रही हैं।

सतत विकास, विकास की संकल्पना का संशोधित रूप है। यह ऐसा विकास है जो मानव समाज की तात्कालिक आवष्यकताओं की पूर्ति ही न करे, वरन् स्थायी तौर पर भावी पीढ़ी के लिए भी विकास का आधार प्रदान करे। संपोषणीय विकास का तात्पर्य ऐसी विकास पद्धति से है जिसके द्वारा भावी पीढ़ी की आवश्यकतापूर्ति की क्षमता से सहयोग किए बिना ही वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो सके। इस प्रकार सतत विकास संसाधनों के सम्यक् बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग, उपभोग तथा संरक्षण पर बल देता है ताकि पर्यावरणीय तत्वों की गुणवत्ता बनी रहे, उनमें न्यूनतम हस्तक्षेप हो और भावी पीढ़ी के लिए वे सुरक्षित रह सकें।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत आलेख का उद्देश्य बिहार राज्य के भागलपुर प्रमण्डल के अन्तर्गत बाँका जैसे ग्राम-बहुल, कृषि-प्रधान, पिछड़े जिले में उपलब्ध संसाधनों के उपयोग का आकलन करना है तथा उनके संरक्षण हेतु रणनीति तैयार करना है।

अध्ययन क्षेत्र एवं समस्या-कथन

24°32' उत्तरी अक्षांश से 25°7' उत्तरी अक्षांश तथा 86°30' पूर्वी देशान्तर से 87°11' पूर्वी देशान्तर के मध्य अवस्थित बाँका जिला मध्य गंगा मैदान के द०-पू० भाग में भागलपुर प्रमण्डल के अन्तर्गत स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 3020 वर्ग कि०मी० है। इस जिले की परिसीमा

दक्षिण में तथा पूरब में झारखण्ड राज्य की सीमा से संलग्न है। इसकी कुल जनसंख्या 2034763 (2011) है। इसके अन्तर्गत 11 अंचल हैं।

यह जिला एक ग्राम-बहुल, कृषि-प्रधान पिछड़ा जिला है, जहाँ 80 प्रतिशत आबादी आज भी प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न है। यहाँ की आबादी में मध्य एवं निम्न आय वर्ग के लोगों की बहुलता है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों की जनसंख्या की अधिकता वाले इस जिले में मिट्टी, जल, वन एवं कुछ मात्रा में खनिज संसाधनों की उपलब्धता है। जनसंख्या की बढ़ती दर प्राकृतिक संसाधनों पर निरन्तर भार डाल रही है, संसाधनों के ह्रास से पर्यावरण अवनयन में वृद्धि देखी जा रही है। फलस्वरूप सतत विकास हेतु पर्यावरण प्रबन्धन की महती आवश्यकता है ताकि भावी पीढ़ी के लिए संसाधन-पर्यावरण सम्बन्ध बना रहे। संसाधनों के समुचित उपयोग द्वारा ही जिले का सम्यक् क्षेत्रीय नियोजन संभव है जिससे निवासियों की सामाजिक-आर्थिक प्रगति सुनिश्चित हो सकती है।

विधितंत्र

अध्ययन की विधि विश्लेषणात्मक एवं मौलिक है। अध्ययन-सामग्री की प्राप्ति प्रतिष्ठित लेखकों की पुस्तकों, संदर्भ ग्रन्थों, प्रतिवेदनों के आधार पर की गई है। आंकड़ों के स्त्रोत मुख्यतः द्वितीयक एवं प्राथमिक हैं।

भौतिक एवं मानवीय पर्यावरण

बाँका जिला का उत्तरी भाग उर्वर जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है जहाँ उत्तरी से आनेवाली गंगा नदी द्वारा लाये गए निक्षेप का प्रसार है। दक्षिण से निकलनेवाली चांदन, चीर, वडुआ, गेरूआ नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी का दक्षिणी मैदानी भाग पर विस्तार है। बाराहाट, रजौन, धोरैया, अमरपुर तथा शंभुगंज प्रखण्ड के अन्तर्गत उपजाऊ भूमि पर धान प्रमुख फसल के रूप में उगाई जाती है। रजौन तथा अमरपुर अंचल की मुख्य फसल कतरनी धान है। अमरपुर में गन्ना प्रमुख फसल हैं, किन्तु इस जिले का दक्षिणी भाग ऊसर तथा बंजर है। चांदन, कटोरिया, बौंसी, बेलहर, फुलीडुमर का अधिकांश भाग कृषि के लिए अनुपयुक्त है। यहाँ पथरीली तथा चट्टानी मिट्टी है, भूमि का यथेष्ट उपयोग बाधित है।

जल संसाधन की दृष्टि से यह जिला समस्या ग्रस्त है। यहाँ भूमिगत जल की मात्रा कम है, धरातलीय जल के रूप में नदियों से प्राप्त जल भी अपेक्षित नहीं है। नदियाँ बरसाती हैं, जिसका जल संचाई के लिए पर्याप्त नहीं है। नदियों से बालू उत्खनन बड़े पैमाने पर होता है फलस्वरूप नदियाँ खेतों तक सिंचाई की सुविधा प्रदान करने में सक्षम नहीं है। भूमिगत जल में आर्सेनिक एवं फ्लुराइड जैसे विशाक्त तत्वों की मात्रा विद्यमान है जिसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

बाँका जिले में पत्थर की कटाई तथा भूमि के अन्दर कहीं-कहीं कुछ मात्रा में खनिज निकाले जाते हैं जिसका प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। यहाँ वन-संसाधन के नाम पर फलदार वृक्ष पाये जाते हैं। वन-क्षेत्र की दृष्टि से वनों का विस्तार सीमित है, वनों की कटाई से वन-क्षेत्र वीरान हो रहे हैं, फलस्वरूप वायु-प्रदूषण तीव्र है।

मानव संसाधन की दृष्टि से यह जिला बिहार राज्य में 25वां स्थान रखता है। मानव-जनसंख्या का वितरण असमान है। उर्वर मिट्टी, जल संसाधन तथा कृषियुक्त भागों में जनसंख्या-घनत्व अधिक है, अधिवास सघन है किन्तु द० पठारी क्षेत्रों में जनसंख्या विरल है, कटोरिया, चानन अंचल के बड़े भाग वीरान एवं जलशून्य है। जहाँ तक मानव-संसाधन का विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्नता का प्रश्न है तो कृषि एवं पशुपालन प्रमुख उद्यम है। द्वितीयक कार्य के रूप में कुटीर एवं लघु उद्योग संचालित है। गन्ना उद्योग, चावल मिल, वस्त्र निर्माण, क्रसर मशीन, लकड़ी चिराई तथा लघु इंजीनियरिंग आदि के व्यवसाय प्रचलित हैं। कृषि के अतिरिक्त वाणिज्य-व्यापार तथा तृतीयक सेवाओं में जनसंख्या कार्यरत है। कुशल एवं दक्ष श्रमिकों की कमी है, फलस्वरूप उद्यमिता प्रतिक्षण की आवश्यकता है। निवासियों का जनजीवन सामान्य एवं निम्न है। आर्थिक एवं

सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टि से निवासी पिछड़े हैं। फलस्वरूप संसाधनों का समुचित शोषण न कर पाते हैं। आजीविका के लिए उपलब्ध संसाधनों का समुचित रूप से उपयोग न होने से पर्यावारण-ह्रास की स्थिति प्रकट है। सूखा एवं बाढ़ प्रतिवर्ष की घटनाएं हैं।

समस्याएँ एवं संभावनाएँ

इस जिले की प्रमुख समस्या उर्वर भूमि का अभाव है। जल-प्रबन्धन द्वारा खेतों को सिंचाई सुलभ हो सकती है। पेयजल भी एक चुनौतीपूर्ण समस्या है। अधिकांश भागों में स्वच्छ पेयजल अपेक्षित मात्रा में उपलब्ध नहीं है जिसे जल-प्रबन्धन की वैज्ञानिक विधियों द्वारा हल किया जा सकता है। वनों का अत्यधिक विनाश एक बड़ी समस्या है जिसे वृक्षारोपण द्वारा अभियान के माध्यम से दूर किया जा सकता है। हरित एवं स्वच्छ पर्यावरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण एवं सार्थक कदम सिद्ध हो सकता है। अनुर्वर, बंजर, बेकार भूमि पर बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाकर रेशमपालन किया जा सकता है। कुटीर एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने की योजना को आकार देकर सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन संभव है। मानव-संसाधन को उचित प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि वे गैर-कृषि कार्यों में दक्षता से संलग्न हो सकें। नदियों से अधिक मात्रा में बालू उत्खनन पर नियंत्रण आवश्यक है। पत्थरों की कटाई तथा वन-क्षेत्र के विनाश पर प्रतिबंध आवश्यक है। इस प्रकार प्राकृतिक एवं मानवीय संसाानों के समुचित उपयोग एवं प्रबन्धन द्वारा सतत विकास को मूर्त्त रूप दिया जा सकता है। आधारभूत अवसंरचना को विकसित करने में प्राकृतिक संसाधनों से न्यूनतम छेड़छाड़ तथा हरित क्षेत्र प्रसार द्वारा पर्यावरण-ह्रास को नियंत्रित किया जा सकता है।

निष्कर्ष

बिहार राज्य का बांका जिला प्राकृतिक एवं मानवीय दृष्टि से उन्नत नहीं है, किंतु क्षेत्रफल की दृष्टि से यह एक वृहत भूभाग है जहाँ प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग एवं प्रबंधन द्वारा सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। कृषि विकास एवं लघु उद्योगों के विकास द्वारा इस क्षेत्र में गरीबी, बेरोजगारी दूर कर आर्थिक स्वावलंबन तथा सामाजिक विषमता को दूर कर क्रांति लाई जा सकती है, मानव संसाधन विकास तथा पर्यावरण प्रबंधन के माध्यम से अधिकतम प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है।

संदर्भ

1. *मिश्र, आर०पी० (2005) : रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, कनसेप्ट प्रकाशन, नई दिल्ली*
2. *सिंह, एल०आर० (सम्पादित) (1983) : पर्यावरण प्रबन्ध, ज्योग्राफिकल सोसाइटी, इलाहाबाद*
3. *श्रीवास्तव, यू०के० (1999) : रूरल डेवलेपमेंट इन एक्शन, सोमैया प्रकाशन, प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई*
4. *वाल्डविन, जे०एच० (2008): इनवायरनमेंटल प्लानिंग एण्ड मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बुक डिस्ट्रिव्यूटर्स, देहरादून*
5. *राय, आर०के० (1991) : इनवायरनमेंटल मैनेजमेंट एण्ड डेवलपमेंट पालिसीज, हिल ज्योग्रफर, वोल्यूम. नं० 122, पृ० 36-45*
6. *भट्टाचार्य, एस० (2004) : पॉपुलेशन, डेवलपमेंट एण्ड एनवायरनमेंट, इण्यिन मेट्रोपोलिटन सीनेरियो, ज्योग्राफिकल रिव्यू ऑफ इण्डिया, वोल्यूम नं० 4, पृ०सं० 371-80.*